



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2015/ज्येष्ठ 4, 1937

No. 313]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2015 /JYAISTHA 4, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2015

सं. 34/2015—सीमा शुल्क

सा.का.नि. 418(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण भाग—II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) संख्या सा.का.नि. 274 (अ), में प्रकाशित, दिनांक 31 मार्च, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, पूर्व वित्त मंत्रालय और कंपनी मामलों (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 52/2003—सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2003, में निम्नलिखित पुनः संशोधन किया जायेगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में,—

(i) शर्त (3) में, खण्ड (घ) में, उप-खण्ड (I) में, मद (i) और (ii) के लिए, निम्नलिखित मदों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(i) पूंजीगत माल की दशा में, यदि उक्त अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है कि ऐसे माल का, अनुमति-पत्र (एलओपी) की वैध समयावधि के भीतर संस्थापित किया गया है या फिर यूनिट के भीतर उपयोग कर लिया गया है;

(ii) पूंजीगत माल से भिन्न माल की दशा में, यदि उक्त अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है कि ऐसे माल को, अनुमति-पत्र की वैध समयावधि के भीतर भारत से बाहर निर्यात के लिए उत्पादन या माल की पेकेजिंग के संदर्भ में, उपयोग किया गया है या घरेलू खपत में उसकी निकासी की गई है;”;

(ii) शर्त (8) के लिए, निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(8) उक्त अधिकारी के संतुष्ट होने की दशा में, पूंजीगत माल, कच्चा माल, उपभोग्य, पुर्जों, विनिर्मित माल, प्रसंस्कृत या पैकेज, और स्क्रैप या खराब या अवशेष या बेकार वस्तुओं के मामले में शुल्क उद्ग्राह्य नहीं होगा, यूनिट के भीतर सीमाशुल्क प्राधिकारी को सूचित करने के बाद विनष्ट किया गया हो अथवा यूनिट से बाहर सीमाशुल्क प्राधिकारी से अनुमति विनष्ट किया गया हो;

बशर्ते सोने, चांदी, प्लेटिनम, हीरे, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों के विनिर्माण और निर्यात में लगी यूनिट के मामलों में यह शर्त लागू नहीं होगी.”;

(ख) पैराग्राफ 13 में, व्याख्या में, खण्ड (xiv) के बाद, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(xv) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में प्रकाशित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, धारा 3, उप-धारा (ii) के द्वारा अधिसूचना सं. 01/2015-2020, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 में “अनुमति-पत्र (एलओपी)” का वही जो अर्थ विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 6 में निर्दिष्ट है।

[फा. सं. डीजीईपी/एफटीपी/23/2014 ईओयू एंड जीएंडजे]

संजय कुमार, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क, दिनांक, 31 मार्च, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 274 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2003 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 33/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 15 मई, 2015 द्वारा सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 15 मई, 2015 के जरिए प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2015

No. 34/2015-CUSTOMS

G.S.R. 418(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue) No. 52/2003- Customs, dated the 31st March, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 274 (E), dated the 31st March, 2003, namely:—

In the said notification,-

(a) in the opening paragraph,-

(i) in condition (3), in clause (d), in sub-clause (I), for items (i) and (ii), the following items shall be substituted, namely:-

“(i) in the case of capital goods, such goods are not proved to the satisfaction of the said officer to have been installed or otherwise used within the unit, within the period of validity of the Letter of Permission (LoP);

(ii) in the case of goods other than capital goods, such goods as are not proved to the satisfaction of the said officer to have been used in connection with the production or packaging of goods for export out of India or cleared for home consumption within the period of validity of the Letter of Permission (LoP);”;

(ii) for condition (8), the following condition shall be substituted, namely:-

“(8) Subject to the satisfaction of the said officer, duty shall not be leviable in respect of capital goods, raw material, consumables, spares, goods manufactured, processed or packaged, and scrap or waste or remnants or rejects are destroyed within the unit after intimation to Customs authorities or destroyed outside the unit with permission of Customs authorities:

Provided that this condition shall not apply in case of unit engaged in manufacture and export of gold, silver, platinum, diamond, precious and semi precious stones.”;

(b) in paragraph 13, in Explanation, after clause (xiv), the following clause shall be inserted, namely:-

“(xv) “Letter of Permission (LoP)” has the same meaning as assigned in Chapter 6 of the Foreign Trade Policy 2015-20 notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification No. 01/2015-2020, dated the 1st April, 2015.”.

[F. No. DGEP/FTP/23/2014-EOU & G&J]

SANJAY KUMAR, Under Secy.

Note : The principal notification no. 52/2003-Customs, dated the 31st March, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R 274 (E), dated the 31st March, 2003, and last amended by notification No. 33/2015-Customs, dated the 15th May, 2015, published vide number G.S.R 387 (E) dated the 15th May, 2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2015

सं. 30/2015—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 419(अ).—अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्त्र एवं वस्त्र निर्मित वस्तुएं), अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात पर संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार, पूर्व वित्त मंत्रालय और कंपनी मामलों (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 22/2003—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2003 में प्रकाशित किया गया था, को भारत की अधिसूचना, भाग—II, धारा 3 (i) सा.का.नि. 265 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2003 के अंतर्गत निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शर्त (4) में, खण्ड (क) में, उप-खण्ड (i) और (ii) के लिए, निम्नलिखित उप-खण्डों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(i) पूंजीगत माल की दशा में, यदि उक्त अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है कि ऐसे माल का, अनुमति-पत्र (एलओपी) की वैध समयावधि के भीतर संस्थापित किया गया है या फिर उपयोगकर्ता उद्योग के भीतर उपयोग कर लिया गया है;

(ii) पूंजीगत माल से भिन्न माल की दशा में, यदि उक्त अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है कि ऐसे माल को, अनुमति-पत्र की वैध समयावधि के भीतर भारत से बाहर निर्यात के लिए उत्पादन या माल की पेकेजिंग के संदर्भ में, उपयोग किया गया है या घरेलू खपत में उसकी निकासी की गई है;”;

(ख) पैराग्राफ 3 में, खंड (iii) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(iii) पूंजीगत माल, कच्चा माल, उपभोग्य, पुर्जों, विनिर्मित माल, प्रसंस्कृत या पैकेज, और स्क्रेप या खराब या अवशेष या बेकार वस्तुएं, सीमाशुल्क प्राधिकारी को सूचित करने के बाद यूनिट के भीतर विनष्ट हुए हों अथवा सीमाशुल्क प्राधिकारी के अनुमति से यूनिट के बाहर विनष्ट हुए हों:

बशर्ते कि विनीशी के बाद अवशिष्ट, अवशेष या स्क्रेप की, यदि घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी होती है, तो ऐसे माल पर लागू शुल्क लगाया जायेगा:

बशर्ते कि आगे यह प्रावधान सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरे, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों पर लागू नहीं होगा.”;

(ग) पैराग्राफ 13 में, व्याख्या में, खण्ड (xiii) के बाद, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा,

अर्थात् :—

“(xv) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में प्रकाशित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—II, धारा 3, उप-धारा (ii) के द्वारा अधिसूचना सं. 01/2015—2020, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 में “अनुमति-पत्र (एलओपी)” का वही अर्थ है जो विदेश व्यापार नीति 2015—20 के अध्याय 6 में निर्दिष्ट है।

[फा.सं. डीजीईपी/एफटीपी/23/2014—ईओयू एंड जी एंड जे]

संजय कुमार, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना सं. 22/2003—केन्द्रीय उत्पाद, दिनांक, 31 मार्च, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 (i) में संख्या सा.का.नि. 265 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2003 और अंतिम बार संशोधित अधिसूचना सं. 28/2015—केन्द्रीय उत्पाद, दिनांक 15 मई, 2015 द्वारा संख्या सा.का.नि. 388(अ), दिनांक 15 मई, 2015 के जरिए प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2015

No. 30/2015-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 419(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and sub-section (3) of section 3 of Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue) No. 22/2003-Central Excise, dated the 31st March, 2003, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R 265 (E), dated the 31st March, 2003, namely:—

In the said notification,-

- (a) in the opening paragraph, in condition (4), in clause (a), for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely:-

- “(i) in the case of capital goods, such goods are not proved to the satisfaction of the said officer to have been installed or otherwise used within the user industry, within the period of validity of the Letter of Permission (LoP);
- (ii) in the case of goods other than capital goods, such goods as are not proved to the satisfaction of the said officer to have been used in connection with the production or packaging of goods for export out of India or cleared for home consumption within the period of validity of the Letter of Permission (LoP);”;

- (b) in paragraph 3, for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

- “(iii) capital goods, raw material, consumables, spares, goods manufactured, processed or packaged, and scrap or waste or remnants or rejects are destroyed within the unit after intimation to Customs authorities or destroyed outside the unit with permission of Customs authorities:

Provided that the remnants, remains or scrap after such destruction, if cleared into Domestic Tariff Area, applicable duty shall be levied on such goods:

Provided further that this provision shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi precious stones.”;

- (c) in paragraph 13, in Explanation, after clause (xiii), the following clause shall be inserted, namely:-

- “(xiv) “Letter of Permission (LoP)” has the same meaning as assigned in Chapter 6 of the Foreign Trade Policy 2015-20 notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification No. 01/2015-2020, dated the 1st April, 2015.”.

[F. No. DGEP/FTP/23/2014-EOU & G&J]

SANJAY KUMAR, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 22/2003-Central Excise, dated the 31st March, 2003 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R 265 (E), dated the 31st March, 2003 and last amended by notification No. 28/2015-CE dated the 15th May, 2015, published vide number G.S.R. 388(E), dated the 15th May, 2015.